उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार, 30 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 19 फरवरी, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)

2. निधन के निदेश।

3. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012-13 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद रूद्रप्रयाग के ग्राम गगोडू में प्राकृतिक जलस्रोत के साथ पानी का भण्डारण किये जाने हेतु टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोडू, पो0 घोलतीर, जनपद-रूद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

6. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा, ''देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा निर्मित ओवरहेड टैंक से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अशोक कुमार, निवासी-संजय कालोनी, बलबीर रोड़, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के अन्तर्गत पुराने बस अड्डे, गांधी रोड की जमीन के सदुपयोग के सम्बन्ध में'' श्री दिलशाद कुरैशी, निवासी-इनामुल्ला बिल्डिंग, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के गांधी नेत्र चिकित्सालय प्रीतम रोड़ (डालनवाला) का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री महेश रावत, निवासी-प्रीतम रोड़ (डालनवाला) जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

10. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

11. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

12. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

13. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

14. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

15. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

16. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

17. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

18. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

19. वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

(1) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1155126 हजार (रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़ इक्यावन लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(2) संसदीय कार्य मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 404601 हजार (रूपये चालीस करोड़ छियालीस लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(3) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1679415 हजार (रूपये एक सौ सडसठ करोड़ चौरानबे लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(4) आबकारी मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 144772 हजार (रूपये चौदह करोड सैंतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(5) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 11538675 हजार (रूपये एक हजार एक सौ तिरपन करोड़ छियासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(6) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 385018 हजार (रूपये अड़तीस करोड़ पचास लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(7) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5194999 हजार (रूपये पांच सौ उन्नीस करोड़ उन्चास लाख निन्यानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(8) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 14051480 हजार (रूपये एक हजार चार सौ पांच करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(9) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1056739 हजार (रूपये एक सौ पांच करोड़ सड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

(10) मुख्यमंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 5262906 हजार (रूपये पांच सौ छब्बीस करोड़ उनतीस लाख छः हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी **(ख)**)

20. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

21. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

22. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

23. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

24. नियम-105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:- **(15 मिनट)**

> "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाये। "

25. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

26. विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे एवं मानिला महाविद्यालयों को पूर्ण पी0जी0 की मान्यता देने की मांग के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

27. जनपद हरिद्वार के जिला अस्पताल/मेला अस्पताल में डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाईयों के संबंध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, स्वास्थ्य मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :

दिनांक : 18 फरवरी, 2014

(जगदीश चन्द्र)

सचिव।

प्रथम सत्र, 2014
का द्वितीय बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 30 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 19 फरवरी, 2014)

नत्थी ''क''

तारांकित प्रश्न

श्री महावीर सिंह रांगड़
31.12.2013

*01. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आपदा के कारण उत्तराखण्ड प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने गावों का विस्थापन होना है तथा क्या सरकार इसमें भूवैज्ञानिकों की मदद ले रही है ? यदि हां, तो भूवैज्ञानिकों ने अभी तक कितने गावों को विस्थापन हेतु चिन्हित किया है ? क्या सरकार उन गावों का विस्थापन हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

आपदा प्रबन्धन

श्री भीमलाल आर्य
31.12.2013

*02. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की दैवीय आपदा/त्रासदी 2013 से प्रभावित विधान सभा क्षेत्र घनसाली में कुल कितनी भूमि (सिंचित/असिंचित), सिंचाई नहरें, लघु सिंचाई नहरें पेयजल योजनायें (पेयजल निगम, स्वजल, स्वैप, जल संस्थान), विद्युत लाईनें, सम्पर्क मार्ग/पुलिया, वन भूमि सम्पर्क मार्ग/पुलिया, मोटर मार्ग/पुल, आवासीय भवन विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुए तथा कुल कितनी पशुहानि, जनहानि हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि किन–किन विभागों को क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु आवंटित की है एवं क्षतिग्रस्त आवासीय भवन तथा पशुहानि जनहानि होने पर कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

आपदा प्रबन्धन

श्री दलीप सिंह रावत
03.01.2014

*3. क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत लघु सिंचाई की कितनी योजनायें हैं जिनके द्वारा सुचारू रूप से सिंचाई की जा रही है एवं ऐसी कितनी योजनायें हैं जिनके निर्माण में हुई अनियमितताओं की जांच चल रही है ? क्या अनियमितता करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई

श्री नवप्रभात 03.01.2014	*4.	**अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में पंजीकृत एन0जी0ओ0 जो सर्वेक्षण में ज्ञात नहीं हो सकी के विषय मे सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या जनपद पौड़ी तथा अल्मोड़ा में भी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार ने यह आंकलन भी किया है कि राज्य में जो एन0जी0ओ0 कार्य कर हे हैं उन्हे कहा–कहां से वित्त पोषण प्राप्त होता है तथा ऐसे एन0जी0ओ0 जो सर्वेक्षण में अज्ञात रह गये को राज्य सरकार से प्राप्त वित्त पोषण का विवरण क्या है ?	**नियोजन**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 06.01.2014	*5.	क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि रोजगार हेतु महत्वपूर्ण मनरेगा योजना एक ऐसी मांग आधारित योजना है जिसमें कि रोजगार की मांग करने पर प्रदेश के प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो रोजगार चाहता हो उसे 100 दिन का रोजगार देना अत्यन्त आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा या राज्य सरकार की कार्य प्रणाली या कमी के कारण प्रदेश की जनता 100 दिन के रोजगार से वंचित हो रही है ? क्या सरकार पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री महावीर सिंह रांगड़ 06.01.2014	*6.	क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गत वर्ष जून माह में हुई आपदा के दौरान जो शासनादेश मुआवजे के लिए घोषित हुए थे क्या वह शासनादेश सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए थे ? यदि हां, तो क्या सरकार ने धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र में शासनादेश के मुताबिक अभी तक कितने परिवारों को मुआवजा दिया है और किस सापेक्ष में ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हे मुआवजा देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री नवप्रभात 06.01.2014	*7.	**चतुर्थ सोमवार के तारा0 15 में स्थाना0** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के यमुनाघाटी क्षेत्र को जनपद उत्तरकाशी के यमुनाघाटी क्षेत्र से जोड़ने वाले बाड़वाला–जुड्डो मार्ग की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण के लिये आपदा राहत मानकों के अधीन वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन स्तर पर कब प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो वित्तीय स्वीृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो स्वीकृति प्रदान करने का क्या कारण है ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री नवप्रभात 06.01.2014	*8.	**स्थगित।** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को चिन्हित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार के सभी विभागों द्वारा एक ही सूची के आधार पर कार्यवाही की जा रही है या विभाग अपनी योजनओं के लिये बी0पी0एल0 लाभार्थी स्वयं चिन्हित करते हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि विभागों के अलग अलग सूची के आधार पर कार्य किये जाने का क्या औचित्य है ?	**ग्राम्य विकास**

श्री महावीर सिंह रांगड़ 08.01.2014	*9. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी टि0ग0 में गूल/नहरें 16 एवं 17 जून, 2013 की अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार गूल/नहरों का निर्माण करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं, ?	**सिंचाई**
श्री पुष्कर सिंह धामी 08.01.2014	*10. **न्यायालय के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।** क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा टिहरी विस्थापितों को भूमि आवंटन के समय बड़ी मात्रा में हुई प्लाट आवंटन की धांधली में दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या प्लाट आवंटन में हुई धांधली की सी0बी0आई0 जांच करवाई जायेगी ?	**सिंचाई**
श्रीमती विजय बड़थ्वाल 09.01.2014	*11. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि ऋषिकेश के अन्तर्गत गंगा में 2013 में आई बाढ़ से गंगा भोगपुर तल्ला एवं कुनांऊ गांव की तटबन्ध पूर्ण क्षतिग्रस्त होने के कारण गंगा नदी का पानी उपरोक्त गावों में भर गया था ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आगामी बरसात से पूर्व सरकार इन बाढ़ सुरक्षा के कार्यों (तटबन्धों) का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री मयूख महर 22.01.2014	*12. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में रई नामक स्थान पर सिंचाई कार्य हेतु झील बनाने की योजना है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को त्वरित सिंचाई योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त योजना हेतु वित्त विभाग द्वारा राज्यांश जारी करने की सहमति दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री ललित फर्स्वाण 22.01.2014	*13. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अधिकांश पर्वतीय जनपदों में कानून व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राजस्व उप निरीक्षकों के उपर है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि अधिकांश राजस्व उपनिरीक्षकों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या कानून व्यवस्था की मजबूती हेतु राजस्व उपनिरीक्षकों की भर्ती की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
डा0 जीतराम 24.01.2014	*14. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कलजीखाल की ग्राम सभा मरोड़ा के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में किन किन मदो से किन किन योजनाओं का निर्माण कब कब कराया गया है तथा योजनओं के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि का योजनावार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन योजनाओं की कार्यदायी संस्थायें कौन–कौन सी हैं तथा इन योजनाओं के निर्माण में लगाये श्रमिकों की पहचान कर ली गई है ? क्या यह सत्य है कि योजनाओं पर कार्य करने वाले श्रमिकों के नाम भी मस्ट्रोल में अंकित किए गए हैं जो वर्षों से प्रवास में रह रहे हैं अथवा कार्य करने में सक्षम नहीं है ? यदि हां, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और यदि नहीं तो मस्ट्रोल में अंकित श्रमिकों की वास्तविकता की जांच किसके द्वारा की गई है ?	**ग्राम्य विकास**

श्री मदन कौशिक 24.01.2014	*15.	**पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।** क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड में खेलों के समुचित विकास हेतु नये खिलाड़ियों के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा खेल नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खेल**
श्री मदन कौशिक 24.01.2014	*16.	क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश को केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक केन्द्रीय योजना में 90:10 के अनुसार धन आवंटन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या विशेष प्रयास किये हैं ?	**नियोजन**
श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 24.01.2014	*17.	क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के सहसपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत शंकरपुर में सिंचाई नलकूप लगभग 2 वर्ष से खराब है जिस कारण कृषि भूमि बंजर हो गई है और ग्रामवासी/किसान सिंचाई नलकूप लगाये जाने हेतु लगातार संघर्षरत हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षेत्र में सिंचाई नलकूप लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री मदन कौशिक 27.01.2014	*18.	क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के कितने आपदा ग्रस्त ग्रामों को पुनर्वास की आवश्यकता है ? क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई समयबद्ध योजना बनायी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
डा0 जीतराम 27.01.2014	*19.	**विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।** क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं का विवरण क्या है तथा विगत पांच वर्षों में इन कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए गए निर्माण कार्यों का संस्थावार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन निर्माण कार्यों का मूल्यांकन क्या है तथा शासन द्वारा गठित ''अवस्थापना विकास'' को अब तक कितने मूल्य के निर्माण कार्य आवंटित किए गए हैं और इन कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य आवंटित करने का क्या मापदण्ड है तथा राज्य सरकार को इन संस्थाओं को निर्माण कार्य आवंटित करने/करवाने में क्या लाभ/हानि है ?	**नियोजन**
श्री चन्दन राम दास 28.01.2014	*20.	क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड शासन ने विधायक निधि के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों को टेंडर के द्वारा कराये जाने का निर्देश दिया है ? यदि हां, तो विधायक निधि से कराये जाने वाले कार्यों के लिये क्या गाइड लाइन बनी है ? यदि नहीं, तो जनपद अल्मोड़ा में विधायकों द्वारा कार्यों की सूची दिये जाने के बाद भी अधिकारी कार्यदायी संस्थाओं को धन अवमुक्त करने में विलम्ब क्यों कर रहे हैं ? क्या इसके लिये जिम्मेदार अधिकारी पर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**

अतारांकित प्रश्न

श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	01. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत धरमघर–चुचेर–माजखेत मोटर मार्ग का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुबन्ध के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है तथा क्या निर्धारित अवधि के अन्दर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	02. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम से किलपारा–बदियाकोट सड़क का निर्माण अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुबन्ध के अनुसार सड़क निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है तथा क्या निर्धारित अवधि के अन्दर सड़क निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री ललित फर्स्वाण 31.12.2013	03. क्या ग्राम्य विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कें चौरा–भैरूचौपट्टा का मिलान मिसिंग लिंक के तहत गैराड़–बिलखेत होते हुए मुख्य सड़क में मिलाने की कोई कार्य योजना है ? क्या उक्त गांव कोर नेटवर्किंग के तहत चयनित है ? यदि हां, तो कब तक जनहित में उक्त सड़क का मिलान कोर नेटवर्किंग के तहत मुख्य सड़क से जुड़ जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री ललित फर्स्वाण 31.12.2013	04. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जनपद के कपकोट विधान सभा क्षेत्र में उतरौंडा–लीली मोटर मार्ग जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मोटर मार्ग बनने के कारण ग्राम पोलिंग सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त हो गयी है ? क्या यह सत्य है कि उक्त ग्राम की कुल खेती की लगभग 80 प्रतिशत भाग इसी क्षतिग्रस्त नहर से सिंचाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त नहर को अविलम्ब बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?	**ग्राम्य विकास**
श्री ललित फर्स्वाण 31.12.2013	05. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के कपकोट विधान सभा क्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 7 खाद्यान गोदामों के ग्रामीण क्षेत्रों में पैदल मार्ग से उगियां, बदियाकोट, खाती, वाछम तलाई, बघर, मल्खडुगर्चा से राशन ले जाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गोदामों में सहायक खाद्य निरीक्षकों की तैनाती हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**
श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 01.01.2014	06. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में किस श्रेणी के राशन कार्ड धारक को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माध्यम से मिट्टी तेल वितरित किया जाता है और कितना ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि दुकान के डीलर को कार्ड धारकों की संख्या के अनुपात से सरकारी गोदाम से पर्याप्त मात्रा में मिट्टी तेल मिल पा रहा है जिससे सभी संबंधित कार्ड धारकों को मिट्टी तेल मिल सके ?	**खाद्य**

श्री विक्रम सिंह नेगी 02.01.2014	07. क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तराखण्ड पंचायतीराज एक्ट बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पंचायतों को 29 विभाग सौंपने जा रही हैं ? यदि हां, तो अब तक कौन कौन से विभाग पंचायतों को सौपे गये हैं तथा कितने सौंपे जाने बाकी हैं ?	**पंचायती राज**
श्री नवप्रभात 02.01.2014	08. क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के डाकपत्थर में स्थित सिंचाई विभाग चिकित्सालय को स्वास्थ्य विभाग द्वारा हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?	**सिंचाई**
श्री चन्दन राम दास 02.01.2014	09. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में मण्डलसेरा के पास सरयू नदी के किनारे क्षतिग्रस्त इलाके में टूटफूट व नदी के कटाव से हुई क्षति का पुनः निर्माण करने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	**सिंचाई**
डा0 जीतराम 03.01.2014	10. **पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में 59 ऐसी बस्तियां हैं जो कोर नेटवर्क में त्रुटिवश संयोजित दर्शायी गयी है जबकि वास्तविक रूप में यह बस्तियां असंयोजित हैं ? यदि हां, तो ऐसी बस्तियों को संचोजित किये जाने के संबंध में की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक इन 59 बस्तियों को मोटर मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?	**ग्राम्य विकास**
डा0 जीतराम 06.01.2014	11. **पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में खण्ड विकास अधिकारियों तथा ग्राम्य पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है और ये पद कब कब से रिक्त चले आ रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति/तैनाती की जायेगी ?	**ग्राम्य विकास**
श्री महावीर सिंह रांगड़ 06.01.2014	12. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत अलमस के साटागाड़ नामक तोक में सरकार नलकूप लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 03.01.2014	13. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की किसी तहसील का नाम क्षेत्रीय जनता के आग्रह पर देश की आजादी में शहादत देने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के नाम से करने पर सरकार विचार करेंगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नाम परिवर्तन हेतु भारत सरकार के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार द्वारा राज्य गठन के पश्चात् आज समय तक इस प्रकार के कितने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गए हैं तथा उनका विवरण क्या है ?	**राजस्व**

श्री नवप्रभात 03.01.2014	14. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून की तहसील विकास खण्ड विकासनगर में लांघा–मटोगी मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था ? यदि हं, तो किस वर्ष में ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उस समय के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रावधानों में सड़क निर्माण तथा रख रखाव के क्या निर्देश थे तथा इस सड़क के डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
श्री महावीर सिंह रांगड 06.01.2014	15. क्या सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण मंत्री अवगत हैं कि उत्तराखण्ड के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ बाजार में नदी में बाढ़ सुरक्षा का कार्य स्वीकृत है ? यदि हां, तो इसमें सरकार कार्य प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**
श्री विक्रम सिंह नेगी 02.01.2014	16. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्रीड़ा स्थल न होने के कारण क्षेत्र के नौजवानों सड़कों पर क्रिकेट, बालीबाल, दौड़ आदि अन्य खेल खेलते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तराखण्ड के 670 न्याय पंचायतों में एक एक मिनी स्टेडियमों का निर्माण करेंगी ? क्या मंत्री जी भी बतायेंगे कि प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में पड़िया, पाचरी एवं सेमण्डीधार में मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु धनराशि निर्गत की जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?	**खेल**
श्री मयूख महर 20.12.2013	17. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार किन किन कार्यों हेतु भूमि अधिगृहित कर सकती है ? क्या अधिग्रहण के उपरान्त उक्त क्षेत्र में स्थिति पैमाईशी रास्तों, मंदिरों एवं अन्य पूर्व निर्मित सार्वजनिक योजनाओं को बन्द कर दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्र की जनता के लिये उक्त कार्यों हेतु सरकार क्या वैक्लपिक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
श्री भीमलाल आर्य 30.12.2013	18. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम प्रहरियों को वेतन प्रदान करने हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**राजस्व**
श्री नवप्रभात 06.01.2014	19. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा प्रदेश में कितनी बाढ़े सुरक्षा योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई तथा उनकी लागत क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस स्वीकृत योजनाओं का जनपदवार विवरण क्या है ?	**सिंचाई**
श्री महावीर सिंह रांगड़ 08.01.2014	20. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड के ग्राम विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0 के कर्मियों को राज्य कर्मचारी घोषित किये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**

श्री ललित फर्स्वाण 16.01.2014	21. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि बागेश्वर जनपद में आयी आपदा से हुये नुकसान के पुनः निर्माण व क्षतिपूर्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा शासन को प्रेषित 42 करोड़ रूपये की धनराशि के प्रस्तावों के सापेक्ष जनपद को मात्र 6 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर को शेष धनराशि कब तक आवंटित की जायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री मयूख महर 23.01.2014	22. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिथौरागढ़ जनपद हेतु स्पोर्टस कालेज की स्वीकृति के उपरान्त शासनादेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य हेतु ग्राम लेलू में भूमि उपलब्ध हो चुकी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि खेल विभाग जारी शासनादेश के परिपेक्ष्य में पिथौरागढ़ जनपद हेतु स्वीकृत स्पोट्र्स कॉलेज बनाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खेल**
डा0 जीतराम 23.01.2014	23. क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत नन्दकेसरी जोला मोटर मार्ग को पंतनगर, जडेरा, बैनाली थराली जिला चमोली गांव तक जोड़ने हेतु विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**
डा0 जीतराम 23.01.2014	24. **तृतीय मंगल के अता0 11 में स्थाना0** क्या नियोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2011–12 तथा वर्ष 2012–13 और वर्ष 2013–14 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष कब कब कितनी धनराशि किस किस विभाग को अवमुक्त की गई है ? क्या यह सत्य है कि वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष स्वीकृत योजनाओं के निर्माण हेतु यथासमय धनअवमुक्त न किए जाने के संबंध में जनपद की प्रभारी मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो शासनादेश द्वारा की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा स्वीकृत धनराशि यथासमय अवमुक्त न किए जाने के कारण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि यथासमय अवमुक्त किए जाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?	**नियोजन**
श्री चन्दन राम दास 23.01.2014	25. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर जिला मुख्यालय के लिए खेल स्टेडियम स्वीकृत है ? यदि हां, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण की क्या कार्यवाही हो रही है ? उक्त स्टेडियम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा इसका विवरण क्या है ?	**खेल**
श्री मालचन्द 24.01.2014	26. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार गंगा प्राधिकरण के अनुसार यमुना प्राधिकरण बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**सिंचाई**

श्री मालचन्द 24.01.2014	27. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत नौगांव, पुरोला, मोरी में क्षेत्रीय ग्रामीण शरद ऋतु में पशुओं तथा भेड़ बकरियों के वास्ते सूखे पशु चारे व घास–भूस का संरक्षण कर घरों में सुरक्षित रखते हैं जो आगजनी की दृष्टि से बहुत विनाशकारी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सूखे पशु चारे व घास–भूस के रख रखाव के लिए पर्वतीय क्षेत्र में अन्य कोई उचित व्यवस्था करेगी जिससे घर एवं गांवों की सुरक्षित रखा जा सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री चन्दन राम दास 24.01.2014	28. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के गरूड़ में बैजनाथ झील का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा तथा इस पर अभी तक कितनी धनराशि खर्च हो गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्माणाधीन झील से किन–किन नहरों व कितने हैक्टेयर भूमि सिंचित किये जाने का प्रस्ताव है ?	**सिंचाई**
श्री चन्दन राम दास 24.01.2014	29. क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर जिले के विकासखण्ड गरूड़ में सिंचाई की कितनी नहरें संचालित हैं तथा संचालित नहरों में कितनी नहरें बंद हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कितनी नहरों में सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है ?	**सिंचाई**
श्री दलीप सिंह रावत 24.01.2014	30. **चतुर्थ सोमवार के अता0 27 में स्थाना0।** क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010 में जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आपदा के कारण बहे बंजादेवी/झर्त पुलों हेतु लोक निर्माण विभाग को धन आवंटित न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री चन्दन राम दास 28.01.2014	31. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में वर्ष 2013 में आपदा प्रबन्धन हेतु कितनी धनराशि आवंटित हुई ? क्या मंत्री जी आवंटित धनराशि में सभी मदों में जनपद की विकासखण्ड वार आवंटित धनराशि का विवरण देने का कष्ट करेंगे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि आवंटित धनराशि विधानसभावार वितरित की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 29.01.2014	32. **स्थगित।** क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा जो विकास कार्यों हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय को विधायक निधि या अन्य योजनाओं का धन अवमुक्त किय जाता है वह लम्बे समय तक खर्चा न होने पर उस पर ब्याज मिलता है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2011–12, 2012–13 व 2013–14 की ऐसी ब्याज राशि जिलेवार विवरण देने पर विचार करेगी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस अवधि की राशि का क्या उपयोग किया गया तथा उसका जिलेवार योजना सहित विवरण देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**ग्राम्य विकास**

श्री दलीप सिंह रावत 29.01.2014	33. क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लैंसडौन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रिखणीखाल एवं नैंनीडांडा में नियमित मिट्टी तेल आपूर्ति न होने के क्या कारण हैं ? क्या विभाग की लापरवाही इसका कारण हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति**
श्री मालचन्द 29.01.2014	34. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत अतिवृष्टि/आपदा से ग्रसित ग्रामों कलाप, नुराणू, बिगराडी, सरबडियार, ओसला, पावणी, गंगाड, ढाटमीर, सरबडियार का विस्थापन कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री चन्दन राम दास 29.01.2014	35. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागेश्वर जिले में विगत 3 वर्षों में कितने लोगों को विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं में लाभान्वित किया गया है ? क्या मंत्री जी धनराशि आवंटन का विवरण एवं समय समय पर वित्त पोषित एवं आच्छादित यूनिटों का समय समय पर विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है ? यदि हां, तो कितनी बार ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खाद्य**
श्री चन्दन राम दास 29.01.2014	36. **पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।** क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में जिला मुख्यालय के लिए खेल स्टेडियम स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो इस स्टेडियम के निर्माण की क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस स्टेडियम के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है तथा इसका विवरण क्या है ?	**खेल**
श्रीमती सरीता आर्या 30.01.2014	37. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के ग्राम सभा भूमियाधार तोक खूपी जिला नैनीताल में 2010 तथा 2013 में जो आपदा आई उससे क्षेत्रवासियों को भूस्खलन से काफी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों के विस्थापन हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**आपदा प्रबन्धन**
श्री दलीप सिंह रावत 30.01.2014	38. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सरकार द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में मिनी स्टेडियम बनाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**खेल**

नत्थी- ''ख''

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्याः- 08 आबकारी विभाग, 10 पुलिस एवं जेल विभाग, 14 सूचना विभाग, 21 ऊर्जा विभाग, 22 लोक निर्माण विभाग, 23 उद्योग विभाग, 27 वन विभाग।

प्रस्तावक का नाम	प्रस्ताव का प्रारूप
1. श्री अजय भट्ट 2. श्री तीरथ सिंह रावत 3. डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'' 4. श्री हरबंस कपूर 5. श्री बिशन सिंह चुफाल 6. श्री मदन कौशिक 7. श्री बंशीधर भगत 8. श्रीमती विजय बड़थ्वाल 9. श्री हरभजन सिंह चीमा 10. श्री अजय टम्टा 11. श्री चन्दन राम दास 12. श्री गणेश जोशी 13. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 14. श्री अरविन्द पाण्डेय 15. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल 16. श्री दान सिंह भण्डारी 17. श्री मालचन्द 18. श्री राजेश शुक्ला 19. डा0 प्रेम सिंह राणा 20. श्री भीम लाल आर्य 21. श्री चन्द्रशेखर 22. श्री पूरन सिंह फर्त्याल 23. श्री संजय गुप्ता 24. श्री आदेश चौहान 25. श्री दलीप सिंह रावत 26. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर 27. श्री महावीर सिंह रांगड़ 28. श्री पुष्कर सिंह धामी 29. स्वामी यतीश्वरानन्द	सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।